

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

DATED

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, MAY 31, 2023

हिन्दुस्तान

नई दिल्ली, बुधवार, 31 मई 2023

Govt Planning To Build Regular Jail At Narela

To Come Up Near High-Security Prison Complex

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: Delhi government has decided to build a regular jail along with a high security prison complex in northwest Delhi's Narela.

As per the initial proposal, Narela jail, which will be spread over 40 acres, was to have a prison complex for 250 high-risk prisoners, including terrorists and hardened criminals. According to officials of Delhi government's home department, the proposed prison complex will have enough space to build a separate jail for undertrials and those convicted for white collar and petty crimes.

A senior official said the Union ministry of home affairs, which is funding the construction of Delhi's fourth prison complex, has given its approval to build a separate jail for other prisoners, which may have the capacity to accommodate 1,800-2,000 inmates.

"This will help us decongest the other three prison complexes. The majority of these inmates are undertrials," said an official, adding that the total capacity of the three prison complexes was a little over 10,000, while more than 18,000 prisoners were lodged there.

While the high-secured prison complex for hardened criminals will have a wheel-and-spoke design similar to that of Andaman's Cellular



File photo

Officials said the move would help in decongesting the other three crowded prison complexes, including Tihar, to some extent

AN OFFICIAL SAYS

The total capacity of the three prison complexes is a little over 10,000, while more than 18,000 prisoners are lodged there

Jail, officials said the Public Works Department will soon be roped in to prepare the design for the regular jail.

The prison complex will be built in two phases, with the deadline for the first phase likely to be in the middle of 2024. Delhi government's prison department has already got possession of the land from the Delhi Development

Authority (DDA).

The prison complex will be constructed with modern security features, with an automated locking system that will be triggered in cases of riots or in-prison clashes. The guards will have body-worn cameras, said an official.

"Currently, padlock systems are in use in the prisons at Tihar, Rohini and Mandoli. In an automated locking system, jail staff can open or lock doors after pressing a button," the official explained.

Another official added that the cells would be built in such a way that high-risk inmates don't get an opportunity to see or talk to each other. "We want to ensure that they do not form gangs inside," the official said.

झुग्गियां हटाने पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

अदालत से

2020 में एनडीआरएफ को दी गई थी भूमि

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) को उसके मुख्यालय के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर बसी झुग्गी बस्ती को हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने तोड़फोड़ की कार्रवाई दो जून के बजाय 15 जून को करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने वसंत विहार में स्लम क्लस्टर प्रियंका गांधी कैप के निवासियों की ओर से दाखिल याचिका पर यह निर्देश दिया है। उन्होंने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूसआईबी) से याचिकाकर्ताओं के पुनर्वास के लिए प्रतिवेदन/मांग पर विचार करने और इस बीच उन्हें एक अस्थायी आश्रय में स्थानांतरित करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता के वकील

न्यायालय को बताया गया कि डीडीए द्वारा 2020 में एनडीआरएफ को यह विवादित भूमि आवंटित की गई थी और वर्तमान में बल का मुख्यालय पट्टे के परिसर में स्थित है, जिसके लिए किराए के रूप में करोड़ों रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि एनडीआरएफ मुख्यालय के निर्माण को रोक नहीं जा सकता है, लेकिन पक्षकारों के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

ने कहा कि इस कैप में पिछले तीन दशकों से लोग रहे हैं, ऐसे में 2015 की पुनर्वास नीति के तहत यहां रह रहे लोग पुनर्वास के हकदार हैं। एनडीआरएफ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि मुख्यालय का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।

NAME OF NEWSPAPERS

DATED

Panel Has Conveyed To SC Its Plan To Resume Visits

To improve saleability of the new flats, DDA has undertaken various remedial measures, including improvement of transport infrastructure, construction of Urban Extension Road -II, permitting amalgamation of flats, allotment on first-come, first-served basis and some concession to the purchasers.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | बुधवार, 31 मई 2023

जून में DDA ला रहा 23 हजार फ्लैट

ज्यादातर LIG और EWS कैटेगरी के ये फ्लैट्स नरेला में होंगे, पहले मई में आनी थी स्कीम

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जून में 23,000 फ्लैटों की स्कीम ला सकता है। पहले इस स्कीम को मई में ही लाया जाना था, लेकिन मई में बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकी जिसके कारण हाउसिंग स्कीम में देरी हुई। अब जून में होने वाली बोर्ड मीटिंग में इसे रखे जाने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, जून के पहले हफ्ते में डीडीए की बोर्ड मीटिंग होने की संभावना है। डीडीए की तरफ से इस हाउसिंग स्कीम को बोर्ड मीटिंग में रखने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।

डीडीए के एक अधिकारी के अनुसार, इस स्कीम में ज्यादातर फ्लैट्स एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स नरेला में होंगे। जून में होने वाली अर्थांश मीटिंग में इस हाउसिंग स्कीम के प्रस्ताव को रखा जाना है। स्कीम इस मीटिंग में अप्रुव होने के तुरंत बाद लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके बाद लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि



40,000

फ्लैट नरेला, द्वारका, जसोला में तैयार हैं, करीब 16 हजार नहीं बिक रहे डीडीए के फ्लैट्स

18.10

लाख से 22.8 लाख के करीब कीमतें थीं एलआईजी फ्लैट्स की 2022 की स्कीम में

7.91

लाख से 12.42 लाख के बीच रखी गई थी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की कीमतें

जून के पहले हफ्ते में डीडीए की बोर्ड मीटिंग होने की संभावना, हाउसिंग स्कीम को बोर्ड मीटिंग में रखने की पूरी तैयारियां

इस स्कीम में फ्लैट्स की कीमतें 2022 की स्कीम से मिलती-जुलती ही रहेंगी। हालांकि अंतिम कीमतें स्कीम लॉन्च होने के बाद ही पता चलेंगी। 2022 की स्कीम में एलआईजी फ्लैट्स की कीमतें 18.10 लाख से 22.8 लाख के करीब थीं। वहीं

ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की कीमतें 7.91 लाख से 12.42 लाख के बीच रखी गई थीं।

डीडीए के करीब 40 हजार फ्लैट्स इस समय नरेला, द्वारका, जसोला आदि जगहों पर तैयार हैं। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और ये नरेला में

हैं। डीडीए अधिकारी के अनुसार, 16,000 के करीब फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे हैं। लोगों को यहां कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है। इन कमियों को दूर करने के लिए डीडीए ने यहां सड़क समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए

दिल्ली में घर खरीदने का मौका

- पहले मई में ही लाई जाने वाली थी यह स्कीम, लेकिन नहीं हुई डीडीए बोर्ड की बैठक
- अब जून के पहले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें हाउसिंग स्कीम रखे जाने की संभावना

आवेदन बढ़ने की उम्मीद

इस बार की डीडीए स्कीम इसलिए भी खास है, क्योंकि नए नियम के तहत वे लोग भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास 67 स्क्वायर मीटर या इससे छोटे साइज के फ्लैट या प्लॉट हैं। अभी तक राजधानी में ऐसे लोग डीडीए की स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते थे, जिनके पास पहले से घर हैं।

कदम उठाए हैं। रिठाला-बवना-नरेला में प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के बनने से इन फ्लैट्स की डिमांड बढ़ने की संभावना है। इससे यहां कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी।

ऐसे मामले दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं : कानूनी जानकार

'सरकारी एजेंसियों के लिए बारापूला हादसे की जिम्मेदारियों से बच पाना मुश्किल'

Prachi.Yadav@timesgroup.com

चाहे पीडब्ल्यूडी हो या एनएचएआई। बारापूला फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से जुड़ी किसी भी एजेंसी के लिए 26 मई के हादसे की जिम्मेदारी से बच पाना मुश्किल है। जाने माने क्रिमिनल लॉयर

और सीनियर एडवोकेट के के मनन ने कहा कि ऐसे मामले आईपीसी की धारा 304ए में दर्ज होते हैं, जो दंडात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित करते हैं। पुलिस का एक्शन अहम है कि वह किन धाराओं में केस दर्ज कर कौन से सबूत जुटाती है। वहीं, पीडित अदालत से मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

एमसीडी और डीडीए के वकील पैनाल में शामिल रहे एडवोकेट कुश शर्मा ने कहा कि मौजूदा मामला पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का है, जिसने चेतावनी वाला

कोई साइनेज तक नहीं लगाया था। चूंकि, प्रोजेक्ट एनएचएआई का है, इसलिए उसकी भी जवाबदेही बनेगी। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। पीडित परिवार मुआवजा के लिए दावा पेश कर सकते हैं। दंडात्मक कार्रवाई में लापरवाही से मौत का मामला बनेगा। इसमें महज दो साल तक की सजा का प्रावधान है।

वकीलों के मुताबिक, बड़ी कार्रवाई मुआवजे के जरिए तय होगी। जैसा कि 2015 के मिलेनियम पार्क हादसे में हुआ था। पार्क में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदे गए एक गड्ढे में गिरकर 11 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वह स्कूल से पिकनिक मनाने गया था। हाई कोर्ट ने 2018 में इस केस में फैसला सुनाया था। पीडब्ल्यूडी को पीडित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने को कहा था।



HC के दिशा-निर्देश

मिलेनियम पार्क हादसे के बाद HC ने दिल्ली के चीफ सेक्टररी, सीपीडब्ल्यूडी, DDA, PWD, नगर निगम, दिल्ली कंट्रोलमेंट बोर्ड, NDMC, DJB, बिजली कंपनियों, टेलीफोन कंपनियों, पुलिस कमिशनर समेत सभी पब्लिक अथॉरिटीज और लैंड ओनिंग एजेंसियों के लिए निर्देश दिए थे।

- सभी मैनहोल, पिट, होल, टैंक या जमीन पर खुले गड्ढे की नियमित रूप से जांच और रखरखाव हो।
- सभी डिपार्टमेंट को शेड्यूल और प्रोटोकॉल तैयार करना होगा।
- ऐसी जगहों से आम जनता को दूर रखा जाए, चेतावनी वाले बोर्ड के जरिए ऐसी जगहों के बारे में लोगों को सूचित करें। हो सके तो सभी गड्ढों को ढंके।

31 मई, 2023 दैनिक जागरण

7

23 हजार फ्लैटों की योजना लाएगा डीडीए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जून में अपनी अगली आवासीय योजना लॉन्च करेगा। बोर्ड बैठक में जून के पहले सप्ताह में संभावित योजना को स्वीकृति भी मिल जाने के आसार हैं। तभी इन फ्लैटों की कीमतें तय की जाएंगी। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि इस आवासीय योजना में निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लगभग 23 हजार नवनिर्मित फ्लैटों की पेशकश की जाएगी। योजना के अधिकांश फ्लैट नरेला में हैं। उन्होंने कहा कि फ्लैटों का आवंटन कम्प्यूटरीकृत ड्रा से किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक आवास योजना को प्राधिकरण की बैठक में मंजूरी मिलने पर शुरू किया जाएगा। यह योजना पहले मई में शुरू होनी थी लेकिन प्राधिकरण की बैठक नहीं होने से मामला लटका रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER

नई दिल्ली। बुधवार • 31 मई • 2023

साम्प्रदायिक
सहारा



विश्वास नगर इलाके के कस्तूरबा नगर में डीडीए की कार्रवाई से डरकर अपने मकान तोड़ते लोग।

फोटो : एसएनबी

डीडीए की कार्रवाई के खौफ से खुद ही तोड़े मकान

नई दिल्ली (एसएनबी)। विश्वास नगर इलाके के कस्तूरबा नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ मंगलवार से की जाने वाली डीडीए की कार्रवाई के डर से लोगों ने खुद ही अपने भवन गिराने शुरू कर दिए हैं।

गौरतलब है कि कस्तूरबा नगर में लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके जो मकान बना लिए थे, उन पर कार्रवाई करने के लिए 22 मई को कोर्ट के आदेश पर डीडीए प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा था। उस दौरान भावन में रहने वालों ने डीडीए की कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया था। पाय की शिवम एन्क्लेव में पत्थर भी फेंके गए थे, जिसकी वजह से पुलिस की 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थीं। डीडीए द्वारा की जा रही कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति कोर्ट में चला गया और कोर्ट से आग्रह किया कि गर्मी के चलते इन भवनों में रहने वाले लोग और उनके बच्चे रोड पर आ जाएंगे, इसलिए कुछ समय की मोहलत दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने 29 मई तक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, ताकि

लोग अपना समान और बच्चों को दूसरी जगह ले जा सकें। शिवम एन्क्लेव के पूर्व प्रधान शंटी घोवर ने बताया कि 30 मई को अवैध रूप से बने इन भवनों पर डीडीए की कार्रवाई करनी थी। डीडीए की कार्रवाई के डर से इन भवनों में रहने वाले लोगों ने खुद ही अपने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया।

स्थिति को देखते हुए विवेक विहार पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर पहुंच गई, ताकि कोई हंगामा खड़ा न हो। यह भी जानकारी मिली है कि इन मकानों में रहने वाले लोगों ने विधायक ओमप्रकाश के कार्यालय पर जाकर हंगामा भी किया, लेकिन विधायक कार्यालय में मौजूद नहीं थे।

गौरतलब है कि 18 ब्लॉक विश्वास नगर से निकलने वाली सड़क, जो शिवम एन्क्लेव से होते हुए विवेक विहार रोड पर निकलती है, इस मार्ग पर कस्तूरबा नगर में अवैध रूप से झुग्गी वालों ने अतिक्रमण कर मकान बना लिए थे। इन सभी मकानों को कोर्ट के आदेश पर डीडीए को हटाना था।

30 मई को अवैध रूप से बने इन मकानों के खिलाफ डीडीए को करनी थी कार्रवाई

विश्वास नगर के कस्तूरबा नगर इलाके में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों का मामला